I request the Railway Minister and Planning Commission to take this important project without further delay.

(ix) Alleged eviction of tribals by forest department in Madhya Pradesh.

श्री बाबूराव परांजपे (जबलपुर) :—उपाध्यक्ष महोदय मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिलों में विशेष रूप से हिडंवाड़ा, मंडला आदि के हजारों आदिवासी परिवार विगत 25-30 वर्षों से बन विभाग की भूमि पर काश्तकारी कर अपने परिवारों का पालन पोषण करते आ रहें हैं । मध्य प्रदेश बन अधिकारी इस वर्ष खेतों की खड़ी फसल काट कर नष्ट कर रहे हैं । उन आदिवासी कृषकों के साथ मार पीट तथा अत्याचारों की घटनायें भी बढ़ती जा रही है : फोरैस्ट अधिकारियों ने यह बताया की केन्द्र सरकार के आदेश हैं कि वन-भूमि पर काश्तकारी करने वालों को शक्ति के बल पर बेदखल किया जाये । पुलिव द्वारा गिरफ्तार किया जावें तथा अदालतों में मुकदमें चलाए जायें । इसी आदेश के अनुसार कब्जाधारी आदिवासी किसानों से जमीनें छीनी जा रही है ।

मध्य प्रदेश वन अधिकारियों द्वारा विगत 25-30 वर्षों से इन आदिवासियों से मुआवजे तथा जुर्माने के रूप में बहुत बड़ी राशि वसूल की गई है ।

इसलिए केन्द्र शासन से अनुरोध है कि मध्य प्रदेश शासन से वन विभाग के अधिकारियों द्वारा केन्द्र शासन के नाम पर जो अदिवासियों के साथ अत्याचार तथा जमीन से बेदखली की जा रही है उस पर तुरन्त रोक लगाई जायें तथा पूरे प्रकरण के जांच के आदेश पारित किए जायें ।

(x) Relief measures for brought effected tribals of Santhal Parganas in Bihar

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) :—उपाध्यक्ष महोदय मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित विषय की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हुं ।

संथाल परगना में भूख से मरने का सिलसिला आरंभ —

लगातार तीन साल से सूखे से पीड़ित बिहार के संथाल परगना जिले में भूख से मरना शुरू हो गया है । जामताड़ा अनुमंडल के नाला थानान्तर्गत जीवनपुर गांव में एक आदिवासी किसान 28 जुलाई को भूख उसे उतड़प-तड़प कर मर गया ।

संपूर्ण जिला भयंकर अकाल की उस्थिति से होकर गुजर रहा है । स्वयं जिले के उपायुक्त ने भी स्वीकार किया है कि संपूर्ण गोड्डा और जामताड़ा अनुमंडल अकाल की चपेट में हैं । दुमका अनुमंडल के लिट्टी पाड़ा गांव में पहाड़ी आदि वासी पहाड़ों से अस्तर उत्तर कर घर-घर माड़ मागने जाने हैं, लेकिन उन्हें माड़ भी नहीं मिलता ।

बड़े-बूढ़े लोगों का कहना है कि जिले में पिछले साठ वर्षों से ऐसा अकाल कभी नहीं पड़ा । अगर सरकार की ओर से किसी तरह का राहत कार्य नहीं चलाया गया तो भूख से मरने वालों की संख्या में वद्धि होने की आंशका है ।

अकाल पीड़ित दर्जनों ग्रामों का भ्रमण करने के बाद बतयालया गया है कि 50 प्रतिशत से अधिक धान के बिचड़े रोपने के पहले ही सरकार जल चुके हैं । सेर्षा के अभाव के अधिकाश ग्रामों में रोपनी शुरू भी नहीं की जा सकी है । कुछ ग्रामों की एक से पांच प्रतिशत जमीन में किसी प्रकार रोपनी संभव हो सकी है । खेत मजदूरों को कहीं काम नहीं मिल रहा है जिसके कारण वे भयंकर भुखमरी के कगार पर हैं । अगर तुरन्त राहत कार्य शुरू नहीं किया गया तो बड़े पैमाने पर लोग भुखमरी के शिकार होंगे ।

यह भी कहा जाता है कि जामताड़ा में 60 प्रतिशत से भी अधिक धान के बिचड़े जल चुके हैं। उनका कहना है कि जामताड़ा के दर्जनों ग्रामों में धान की रोपनी शुरू भी नहीं हों सकी है । इस प्रकार संपुर्ण जिला अकाल के मुंह में समा चुका है ।

अतः ऐसी प्राकृतिक विपत्ति के समय सरकार से मेरा अनुरोध होगा कि वह अकाल पीड़ित